सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-40 अंक 24 22 दिसम्बर 2025 से 5 जनवरी 2026 मुख्य संपादकः कॉमरेड प्रभास घोष कुल पृष्ठ : 8 मूल्य : 4 रुपये पृष्ठ 1

इंश्योरेंस में 100% एफडीआई के भाजपा सरकार के फैसले का एसयूसीआई (सी) ने किया कड़ा विरोध

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 13 दिसम्बर को जारी बयान में कहा :

"अंधाधुंध निजीकरण के चक्कर में भाजपा की केंद्र सरकार ने अब 34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कोष वाली एलआईसी सहित इंश्योरेंस में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की इजाजत देकर भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों के पूरे निजीकरण का रास्ता खोल दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि इसने लोवर पेड-अप कैपिटल जरूरतों (अधिकृत पूंजी के असल में चुकाये गये हिस्से) के साथ-साथ एक कम्पोजिट लाइसेंसिंग सिस्टम (जनरल और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में कदम रखने के लिए एक परमिट, जिससे नियम आसान होंगे और लागत कम होगी) को भी मंजूरी दी है। बीमा करवाये हुए लोगों को बिना विस्तार से यह बताये कि ये फायदे कैसे मिलेंगे, सरकार का यह दावा है कि इससे क्लेमों का निपटारा तेजी से होगा, उत्पादों के ज्यादा विकल्प मिलेंगे, डिजिटल सर्विस बेहतर होंगी, कम्पीटिशन से चलने वाली कीमतें बढ़ेंगी और मजबूत रेगुलेटरी सुरक्षा मिलेगी। बल्कि इस फैसले से प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां, जो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के मकसद से चलती हैं, ज्यादा मुनाफे वाले शहरी सेक्टर पर ध्यान देंगी, क्लेमों को मनमाने ढंग से मना कर सकती हैं, जिससे कवरेज की कुल लागत पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ सकता है और सरकार के दावे के उलट, पूरी तरह से निजीकरण से बाजार सुदृढ़ होगा, जिसमें सिर्फ कुछ बड़े कारोबारी ही भागीदार होंगे और इस तरह स्वस्थ प्रतियोगिता की कमी से प्रीमियम बढ़ जाएगा। यह साफ है कि ऐसा तरीका विदेशी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लुभाने के लिए अपनाया गया है, जिनका ज्यादातर का मूल उद्गम अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड से है। यह बताना जरूरी है कि अमेरिका जैसे देशों में जहां बीमा उद्योग में कम्पीटिशन बहुत ज्यादा है, वहां बड़ी संख्या में कंपनियां फेल हुई हैं, क्योंकि वे मुनाफा बढ़ाने के लिए क्लेम को मना करने, पेमेंट में देरी करने जैसी गंदी चालें और गलत काम करती हैं। बड़े साम्राज्यवादी देशों में दर्जनों प्राइवेट बीमा कंपनियां हर साल सट्टेबाजी वाले निवेश और गलत कामों की वजह से दिवालिया घोषित की जा रही हैं।

इसलिए हम भाजपा सरकार की ऐसी पूरी तरह से जनविरोधी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हिमायती इस नीति का कड़ा विरोध करते हैं और मेहनतकशों से, चाहे वे किसी भी उद्योग में हों, एक जुझारू एकता कायम करने और इस अंधाधुंध निजीकरण के खतरनाक इरादे को नाकाम करने के लिए एक लगातार संगठित व शक्तिशाली आंदोलन छेड़ने की पुरजोर अपील करते हैं।"

दर्शन और विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

1-6 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका 'मार्क्सवाद और विज्ञान' की पहल पर 'दर्शन और विज्ञान एक अंतर्राष्ट्रीय आलोचनात्मक ज्ञान नेटवर्क की ओर' विषय पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया के पहाड़ी क्षेत्र के एक छोटे से गांव हाइफा में आयोजित हुआ। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रोमानिया, हंगरी, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका से आये प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इनमें कुछ प्रतिनिधि अपने-अपने देशों में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जबकि बाकी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में मार्क्सवादी दर्शन पर शोध कर रहे थे। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड एस. बनर्जी भारत से अकेले प्रतिभागी थे।

सम्मेलन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, विज्ञान के इतिहास लेखन और वर्तमान समाज की विभिन्न समस्याओं के मार्क्सवादी विश्लेषण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कॉमरेड बनर्जी का पूरा भाषण नीचे दिया जा रहा है।

वैज्ञानिक पद्धति के आधार के तौर पर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

समाजवादी खेमे के पतन और विश्व में पूंजीवाद का प्रभुत्व कायम होने के बाद यह प्रचारित किया गया कि मार्क्सवाद विफल हो गया है। मार्क्सवाद के दार्शनिक आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर भी हमले हुए। इसे 'चलन से बाहर', 'अप्रचलित', 'वर्तमान समय के लिए अप्रासंगिक' और सिर्फ इतिहासकारों के शोध व शैक्षणिक-ऐतिहासिक सरोकार का मामला बताया जा रहा है।

हालांकि, विज्ञान इसी दर्शन के आधार पर कार्य करता है। विज्ञान भौतिक जगत के बारे में सच्चाई की खोज करता है और उसके आधार पर प्रकृति कैसे काम करती है, यह जानने-समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए सिद्धांत विकसित करने की कोशिश करता है। विज्ञान में किसी भी अवधारणा को तभी माना जाता है, जब उसे निरीक्षण और प्रयोग के जरिये वस्तुवादी तरीके से स्थापित किया जाता है। निस्संदेह, इन प्रयोगों और अवलोकनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत सोच और दार्शनिक विचार भी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

वंदे मातरम, रवींद्र संगीत और राममोहन राय को लेकर भाजपा नेताओं की बदजुबानी से छिड़ा विवाद!

भाजपा ने 7 नवंबर 2025 को देशभर में 150 जगहों पर देशभक्ति गीत 'वंदे मातरम' के 150वें साल का महोत्सव मनाने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किये। उस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा: "आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकडे किये गये थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजने के बीज भी बो दिये थे।" यह बात वाकई दिलचस्प है (!) क्योंकि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वे असल इतिहास से अनजान लगते हैं। इसलिए उन्होंने आरएसएस-हिंदू महासभा, जो भाजपा के पूर्वज और गुरु हैं, को हमारी आजादी की शानदार लड़ाई के केंद्र में दिखाया और 'वंदे मातरम' गीत को उस साम्राज्यवाद-विरोधी आजादी आंदोलन का मंत्र बताया। क्यों? इसका हम सिलसिलेवार ढंग से खुलासा करेंगे।

वंदे मातरम का इतिहास

मशहूर साहित्यकार बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित, 'वंदे मातरम' पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका 'बंगदर्शन' में प्रकाशित हुआ था। बाद में बंकिमचंद्र ने इस भजन को अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, जबकि रवींद्रनाथ

(शेष पृष्ठ 7 पर)

एसकेएम के राष्ट्रीय नेता और एआईकेकेएमएस के अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान, ओडिशा राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सदाशिव दास और अन्य साथियों पर

जिंदल-पोस्को कंपनी के गुंडों द्वारा हमले व अपहरण की कड़ी निंदा और तुरंत रिहाई की मांग

9 दिसम्बर को ओडिशा के क्योंझर जिले में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सत्यवान

ऑल इंडिया किसान खेत-मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के महासचिव कॉमरेड शंकर घोष ने 9 दिसंबर को जारी बयान में कहा:

"संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रीय नेता और एआईकेकेएमएसएस के अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान, एआईकेकेएमएस के ओडिशा राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सदाशिव दास और अन्य साथियों को जिंदल-पोस्को कंपनी के गुंडे जबरन उठाकर पुलिस थाने ले गए। उन्हें ओडिशा के क्योंझर जिले के तुरुमुंगा थाने में पुलिस हिरासत में रखा गया। यह घटना तब हुई, जब वे ओडिशा के क्योंझर जिले के जमुनापोसी गांव में जिंदल-पोस्को प्रतिरोध मंच द्वारा आयोजित एक सभा से लौट रहे थे।

हमारा दृढ़ मत और विश्वास है कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने गरीब किसानों की कृषि भूमि हथियाने में जिंदल और पोस्को जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मदद करने के लिए यह घिनौनी साजिश रची है।

हम सत्ताधारियों के इस जनविरोधी और किसान-विरोधी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और कॉमरेड सत्यवान और संगठन के अन्य नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं।"

दर्शन और विज्ञान....

(पृष्ठ 1 का शेष)

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम विज्ञान के इतिहास पर नजर डालें, तो हम पायेंगे कि कई जाने-माने वैज्ञानिकों और उनके अपने-अपने वैज्ञानिक समुदायों ने अनजाने में ही अपनी मान्यताओं और दार्शनिक सिद्धांतों के प्रभाव में कई महत्वपूर्ण खोजों के मार्ग में रुकावट डाली है। इसलिए एक सुदृढ़ दार्शनिक नजरिये के बिना विज्ञान की प्रगति मुश्किल है।

विज्ञान के आधार पर विकसित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वह दार्शनिक नजरिया प्रदान करता है, भले ही ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात से वाकिफ न हों। कई लोग मानते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिर्फ 'तीन सिद्धांतों' का एक संग्रह है। लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आने से पहले यांत्रिक भौतिकवाद व अधिभौतिकवादी सोच का बोलबाला था और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को विकसित करने की प्रक्रिया में मार्क्स और एंगेल्स ने इन दोनों विचारधाराओं की कमजोरियों का सूक्ष्म रूप में विश्लेषण किया और वैज्ञानिक खोज का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोण तैयार किया। बाद में लेनिन ने प्रत्यक्षवाद द्वारा उत्पन्न भ्रम के बादल को हटाकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थिति को और मजबूत किया।

द्वंद्वात्मक पद्धति और अधिभौतिकवाद में अंतर

दर्शनशास्त्र में दो प्रमुख विचारधाराओं–भौतिकवाद और भाववाद–में से विज्ञान भाववाद, अधिभौतिकवाद व यांत्रिक भौतिकवाद के विरुद्ध भौतिकवाद के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। विज्ञान इस आधार पर शुरू होता है कि भौतिक जगत का अस्तित्व मानव चेतना से स्वतंत्र है। वैज्ञानिकों के लिए यह मान लेना असंभव होगा कि जिन वस्तुओं का वे अध्ययन कर रहे हैं, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है या वे वास्तव में भाव की किसी अलौकिक सत्ता द्वारा निर्मित हैं।

संसार का अधिभौतिकवादी यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण सभी वस्तुओं की प्रकृति को, उनकी विशिष्टता को पहले से दी हुई, पूर्व निर्धारित और स्थायी-स्थिर मानकर अध्ययन करता है। वे न तो बदलती हैं और न ही विकसित होती हैं। अधिभौतिकवादी यानी आध्यात्मिक चिंतन पद्धति का अनुसरण करने वालों ने प्रत्येक वस्तु को, उसके स्वरूप को 'चीजों को जैसी वे हैं वैसा ही' अध्ययन करने की वकालत की। उनका मानना था कि प्रत्येक वस्तु का एक अंतर्निहित गुण या धर्म होता है, जो उसके अस्तित्व से जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। अधिभौतिकवादी यानी आध्यात्मिक चिंतन ने यह मान लिया कि सभी वस्तुओं की प्रकृति और विशेषताएं शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं और प्रत्येक वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से पृथक माना है।

द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने जोर देकर कहा कि संसार पूर्व निर्धारित गुणों वाली अपरिवर्तनीय वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि भौतिक संसार में हर चीज निरंतर परिवर्तन और विकास के दौर से गुजर रही है। हर पल कुछ चीजों का निर्माण हो रहा है और कुछ का विनाश। इसलिए विज्ञान का कार्य वस्तुओं के परिवर्तन और विकास के क्रम में अध्ययन करना है। वे कैसे अस्तित्व में आती हैं और कैसे विलुप्त होती हैं, उस प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद न केवल चीजों के अध्ययन पर, बल्कि उनके परिवर्तन, निर्माण और विलुप्त होने की प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक महत्व देता है। यह कहता है कि संसार को वस्तुओं के एक जटिल समूह के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे प्रक्रियाओं के जटिल समूह के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके माध्यम से चीजें हर पल बदल रही हैं और वे निर्मित व विलुप्त हो रही हैं। द्वंद्वात्मक विश्व-दृष्टिकोण यह सिखाता है कि चीजें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक-दूसरी पर निर्भर हैं और एक-दूसरी द्वारा निर्धारित होती हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान को कभी भी चीजों को आसपास की दुनिया से अलग-थलग अकेले में अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे चीजों का उनके आपसी संबंधों और अंत:क्रियाओं के संदर्भ में ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। विज्ञान को चीजों के गुणों को उनके आसपास के परिवेश और उनके अस्तित्व की परिस्थितियों से अलग-थलग करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे यह अध्ययन करना चाहिए कि अस्तित्व की स्थितियां, परिवेश के परिवर्तन के साथ चीजों का गुण और उसका चरित्र परिवेश कैसे बदलता है।

न्यूटनोत्तर युग में समाज में यांत्रिक भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रचलित था। यह दृष्टिकोण संपूर्ण विश्व को एक विशाल मशीन के रूप में देखता था, जिसका प्रत्येक भाग अपने विशिष्ट यानी तय नियमों के अनुसार कार्य करता था। मशीन का कोई भी पुर्जा अपने जीवनभर उसी तरह काम करता रहता है। उसकी यांत्रिक प्रक्रिया को निरंतर जारी रखता है। इसलिए यांत्रिक भौतिकवादियों ने पदार्थ के परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश की, जो बदलती न हो, जो शाश्वत हो। उन्होंने यह मान लिया कि भौतिक जगत वास्तव में अपरिवर्तनीय है और हम जो भी परिवर्तन देखते हैं, वे उसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति मात्र हैं, जो यांत्रिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। यांत्रिक भौतिकवाद ने भौतिक जगत के परिवर्तनों को उसी प्रक्रिया के निरंतर दोहराये जाने वाले चक्रों और पुनरावृत्ति के रूप में देखा। एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'प्रकृति की द्वंद्वात्मकता' की भूमिका में कहा, ''लेकिन इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अन्दर एक विशिष्ट प्रकार का सामान्य विश्व दष्टिकोण विकसित हुआ, जिसका केन्द्र बिन्दु यह मत है कि प्रकृति सर्वथा अपरिवर्तनीय है।'' यह प्रकृति को शाश्वत के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति है। यांत्रिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण में संसार ठोस और अविनाशी कणों से बना हुआ देखा गया है। उनका मानना था कि प्रकृति की सभी घटनाओं की व्याख्या इन कणों पर बाह्य बलों की क्रिया और उनके बीच की अन्योन्य क्रियाओं और गतियों के संदर्भ में की जा सकती है। यांत्रिक भौतिकवाद की मुख्य समस्या यह थी कि यह पदार्थ को जड़ पदार्थ मानता था, जिसकी अपनी कोई गति नहीं होती और जिसमें गति बाहर से दी जाती है। उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान के विकास ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि ऊर्जा के सभी रूप वास्तव में 'गतिशील पदार्थ' के अलावा और कुछ नहीं हैं। जब ऊर्जा का एक रूप दूसरे में रूपांतरित होता है, तो गति भी रूपांतरित हो जाती है। गति हमेशा बनी रहती है। गति सर्वव्यापी और शाश्वत है, कुछ भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। इन अवलोकनों के आधार पर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने यह विचार पेश किया कि गतिहीन पदार्थ का अस्तित्व असंभव है और पदार्थ के बिना गति का कोई अर्थ नहीं है। लेनिन ने कहा, ''दुनिया में गतिशील पदार्थ के सिवा और कुछ भी नहीं है और यह गतिशील पदार्थ स्थान और काल के बाहर अस्तित्व में नहीं रह सकता।'' इसलिए पदार्थ की प्रकृति का सही विचार यह है कि गति पदार्थ के अस्तित्व का ढंग है।

यह भी समझा गया कि किसी वस्तु के विभिन्न भागों के बीच बाहरी यांत्रिक बलों की अंत:क्रिया द्वारा किसी वस्तु में होने वाले सभी परिवर्तनों की व्याख्या करना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता, तो किसी पिंड का सम्पूर्ण स्वरूप उसके अलग-अलग भागों के स्वरूप का योग मात्र होता। लेकिन कई वैज्ञानिक खोजों (जैसे कोशिका सिद्धांत) ने सिद्ध कर दिया है कि यह विचार सत्य नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने दर्शाया है कि घटक भागों के एक निश्चित स्तर पर संयोजन और अंत:क्रिया पर उस वस्तु में नए गुण उभर सकते हैं। किसी वस्तु को छोटे-छोटे भागों में तोड़कर और उसे अलग-अलग अध्ययन कर उसके समग्र गुणों और उसके विकास के नियमों को कभी भी सही मायने में नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने वास्तव में विज्ञान को अपचयनवाद/न्यूनीकरणवाद (reductionism) के प्रभाव से मुक्त कर दिया है।

विज्ञान में तीन सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग

जैसे-जैसे विज्ञान का ध्यान पदार्थ के परिवर्तन और विकास के अध्ययन पर केंद्रित हुआ, मार्क्स और एंगेल्स ने दिखाया कि ऐसे अध्ययन के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिए। किसी भी भौतिक इकाई के परिवर्तन और विकास की जांच करते समय निम्नलिखित प्रश्नों का सामना करना पड़ता है।

1. परिवर्तन क्यों होते हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने दिखाया कि किसी भी इकाई में विरोधी शक्तियां या प्रवृत्तियां होती हैं और इनके बीच एकता और द्वंद्व-संघर्ष किसी भी परिवर्तन का मूल कारण है।

2. परिवर्तन कैसे होते हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने दिखाया कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं: मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक परिवर्तन से गुजरते समय एक चरम बिंदु तक पहुंचा जा सकता है, जब वह पिंड एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरता है।

3. गुणात्मक परिवर्तन का परिणाम क्या होता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने दिखाया कि गुणात्मक परिवर्तन अपनी पूर्व अवस्था का निषेध करता है और एक नई अवस्था का जन्म होता है।

क्या आधुनिक विज्ञान इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है? करता है। हालांकि द्वंद्ववाद के ये तीनों सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के आलोक में पूर्णत: प्रमाणित हो चुके हैं, फिर भी वैज्ञानिक साहित्य सामान्यत: भिन्न शब्दावली का प्रयोग करता है, जिससे वैज्ञानिकों को द्वंद्वात्मक सिद्धांतों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक साहित्य अंतर्विरोधों की शब्दावली में बात नहीं करता। किंतु जब भी कोई वैज्ञानिक किसी यांत्रिक प्रणाली में बलों के संतुलन का समीकरण लिखता है, वह अनजाने में ही विपरीतों की एकता को लागू करता है। हमारा कार्य यह है कि वैज्ञानिक को यह बात जानबूझकर करने के लिए प्रेरित करें।

यांत्रिकी के क्षेत्र में, विशेष रूप से न्यूटोनियन यांत्रिकी में कई वस्तुओं से बनी किसी प्रणाली की यांत्रिक अवस्था के परिवर्तन के नियमों को जानने का प्रयास करती है, जिसे सभी परस्पर क्रिया करने वाली वस्तुओं की स्थितियों और वेगों के आधार पर परिमाणित किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के चलने के पथ को जानने के लिए सबसे पहले हमें चंद्रमा और पृथ्वी की प्रारंभिक स्थितियों और संवेगों को जानना होगा और फिर इन दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेन्द्रीय बल के आधार पर समीकरण लिखा जाएगा, जो एक-दूसरे के विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। इस प्रकार ये दोनों बल उस प्रणाली के अंतर्निहित यांत्रिक द्वंद्व को व्यक्त करते हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी प्रणाली में अवस्था का परिवर्तन उन समीकरणों के माध्यम से पूर्वानुमानित किया जाता है, जो वास्तव में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के संतुलन का उपयोग करते हैं। अत: ऐसे समीकरण विपरीतों की एकता को मानकर चलते हैं।

द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह भी सिखाता है कि विरोधी शक्तियों या विपरीतों के बीच द्वंद्व-संघर्ष किसी भी वस्तु के परिवर्तन और विकास का मूल कारण होता है। किसी वस्तु का आंतरिक द्वंद्व यानी अंतर्विरोध किसी वस्तु के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति होता है और बाह्य अंतर्विरोध, बाहरी द्वंद्व यानी बाहरी वस्तुओं का प्रभाव हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होता है और कुछ मामलों में परिवर्तन की दिशा निर्धारित करने में यह निर्णायक भूमिका निभाता है, केवल अंदरूनी द्वंद्व यानी अंतर्विरोध के जरिये ही काम करता है। तारकीय विकास की परिघटना इसका सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब वैज्ञानिक सूर्य जैसे किसी तारे के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, तो वे वास्तव में उस तारे के अंदरूनी द्वंद्व को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तारे का गुरुत्वाकर्षण भीतर की ओर कार्य करता है और उसके पिंड को केंद्र की ओर संकुचित करने का प्रयास करता है। तारे के केंद्र में निरंतर चल रही तापनाभिकीय अभिक्रिया (संलयन) तारे के केंद्र में प्रचंड ऊष्मा उत्पन्न करती है। नतीजतन, अंदरूनी भाग में उच्च दाब उत्पन्न होता है, जो तारे के पदार्थ को बाहर की ओर धकेलता है। यानी तारे के भीतर दो विरोधी बल कार्य करते हैं और तारे का स्थायित्व इन दो विरोधी बलों के संतुलन पर निर्धारित होता है। वैज्ञानिक इस द्वंद्व पर शोध करते हैं, जो वास्तव में विरोधी शक्तियों यानी विपरीतों की एकता के सिवा और कुछ नहीं है।

'मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन और वाइस-वर्सा(vice versa)' का सिद्धांत जीव विज्ञान और समाजशास्त्र में हुई विभिन्न खोजों और भौतिक पिंडों की उस समझ से प्रेरित था, जिसमें किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है (जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में बदलना)। न्यूटोनियन यांत्रिकी सीधे मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों की बात नहीं करती है। किसी प्रणाली की अवस्था और उसकी गतिशीलता में होने वाले मूलभूत गुणात्मक परिवर्तनों को बहुत हाल ही के वर्षों में समझा गया है। भौतिकी में किसी वस्तु की स्थिति में इन गुणात्मक परिवर्तनों का अध्ययन ''प्रावस्था संक्रमण और क्रांतिक परिघटनाओं'' (Phase Transition and Critical Phenomenon) के नाम से किया जाता है। ऐसे गुणात्मक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं धातुओं का चुंबकत्व, अतिचालकता, अतितरलता, बोस-आइंस्टीन संघनन आदि। किसी वस्तु की गति की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन (जैसे, आवर्ती गति से अनावर्ती गति में परिवर्तन) को 'द्विभाजन' कहा जाता है। इन मामलों में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की सर्वव्यापी की ब्रह्माण्डीय प्रायोगिकता फिर से सही सिद्ध हुई है।

द्वंद्ववाद में 'वाइस-वर्सो' को आमतौर पर मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन के अनुक्रम के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो समय के साथ चलती रहती है। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि किसी वस्तु में मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया जब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाती है, जो उस वस्तु में गुणात्मक

(शेष पृष्ठ 6 पर)

विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण (एसईसीआई) शिक्षा के फासीवादी केंद्रीकरण की दिशा में एक कदम

यह शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता पर लगाएगा अंकुश & एआईडीएसओ

ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के महासचिव शिवाशीष प्रहराज ने 14 दिसम्बर को जारी एक प्रेस बयान में कहा:

"उच्च शिक्षा आयोग विधेयक (एचईसीआई), जिसे अब विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक नाम दिया गया है और जिसे 12 दिसंबर 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस विधेयक के जरिये उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं—यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई—को एक ही निकाय में विलय कर उन्हें सीधे केंद्र सरकार के अधीन लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इन संस्थानों की स्वायत्तता को सीमित किया जाएगा। इस नए निकाय के अधिकतर प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। यह निकाय शैक्षणिक नियमन, प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) और पेशेवर मानकों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि वित्तीय एवं अनुदान संबंधी मामलों का संचालन प्रशासनिक मंत्रालय के हाथ में रहेगा।

हम सभी शिक्षा के बजट में लगातार की जा रही कटौतियों, सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे, पाठ्यक्रम के 'युक्तिकरण' के जरिये धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और जनवादी माहौल पर किये जा रहे हमलों तथा केंद्र सरकार की अन्य नीतियों से भली-भांति वाकिफ हैं। यह सब सरकार के वास्तविक इरादों को उजागर करता है। एक ओर सभी के लिए समान, सुलभ और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना और दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण बनाये रखना। इस संदर्भ में यह विधेयक संस्थागत स्वायत्तता पर सीधा हमला है और शिक्षण संस्थानों के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है।

यह उल्लेखनीय है कि जब यह विधेयक पहली बार 2018 में पेश किया गया था, तब छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया था। अब इसके पुन: प्रस्तुतीकरण पर भी छात्रों, शिक्षक संगठनों और शिक्षा के पक्षधर सभी लोगों की ओर से तीव्र विरोध देखने को मिल रहा है। शिक्षा के केंद्रीकरण की स्पष्ट बात करने वाली, घोर शिक्षा-विरोधी एनईपी-2020 को लागू करने के अपने ताबड़तोड़ प्रयासों को जारी रखते हुए भाजपा सरकार ने यह एचईसीआई विधेयक पारित किया है। जुलाई 2020 में एनईपी के लागू होने के बाद से एआईडीएसओ एनईपी-2020 और हर उस शिक्षा-विरोधी और छात्र-विरोधी नीति के खिलाफ जोरदार जन आंदोलन खड़ा कर रहा है। कठिन समय में जोरदार प्रतिरोध की जरूरत होती है और यह समय की मांग है कि सभी छात्र, शिक्षक और शिक्षा-प्रेमी लोग एकजुट होकर शिक्षा के केंद्रीकरण, सांप्रदायीकरण, व्यवसायीकरण और निजीकरण के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन खड़ा करें, जिन्हें एनईपी-2020 के जरिये आक्रामक रूप से लागू किया जा रहा है।

एआईडीएसओ सभी जनवादी, प्रगतिशील और वामपंथी छात्र संगठनों का आह्वान करता है कि वे इस फासीवादी और निरंकुश हुकूमत के इस विधेयक के खिलाफ इस संघर्ष में एकजुट हों, जो हमारी धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, जनवादी और सर्वजनीन शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है।"

एआईपीएफ का तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन सम्पन्न

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : ऑल इंडिया पावरमेन्स फेडरेशन (एआईपीएफ) का तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन 13-14 दिसम्बर को यहां मौलाली सभागार में आयोजित हुआ। इसमें कई चुनौतियों पर चर्चा हुई और बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने पर गहन विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन को अन्य वक्ताओं के अलावा एआईयूटीयूसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉमरेड स्वपन घोष ने भी संबोधित किया।

कोलकाता: सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉमरेड शंकर दासगुप्ता

ऑल इंडिया पावरमेन्स फेडरेशन के तीसरे अखिल भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र की शुरुआत एआईयूटीयूसी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड अशोक दास के भाषण से हुई। प्रतिनिधियों के बीच विस्तार से चर्चा के बाद जनविरोधी स्मार्ट मीटर नीति के खिलाफ और साथ ही मांगपत्र और संवैधानिक संशोधनों पर प्रस्ताव पारित किये गए।

आखिर में सम्मेलन के मुख्य वक्ता, एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने सभा को संबोधित किया।

सम्मेलन ने कॉमरेड के. सोमशेखर को अध्यक्ष और कॉमरेड समर सिन्हा को महासचिव चुना और 12 राज्यों के प्रतिनिधियों को लेकर 67 सदस्यीय अखिल भारतीय कमेटी गठित की गयी।

सरकार द्वारा लेबर कोड लागू किये जाने के खिलाफ

कारखाना मजदूरों ने जुलूस निकाला और इनकी प्रतियां फूंकीं

समालखा (हरियाणा) : बीजेपी-नीत केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक विरोधी व कॉर्पोरेट परस्त चार लेबर कोड को अचानक लागू करने की अधिसूचना जारी करने के खिलाफ ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) के आह्वान पर 5 दिसंबर को यहां औद्योगिक मजदूरों ने कारखाना मजदूर यूनियन के बैनर तले एक विरोध सभा की और जुलूस निकाला।

सभा को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी हरियाणा प्रदेश कमेटी के सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश ने बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल से अब तक मजदूरों के द्वारा बड़े संघर्षों व कुर्बानियों से हासिल 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट परस्त चार लेबर कोड लागू किये हैं।

इन लेबर कोड्स में श्रमिकों के बचे-खुचे वैधानिक अधिकारों को भी छीनने का रास्ता साफ कर दिया गया है। 8 घंटे कार्य दिवस की जगह 12 घंटे कार्य दिवस, मजदूरों का यूनियन बनाने, उसे पंजीकृत कराने,अपने ढंग से चलाने तथा अपनी सामूहिक मांगें मनवाने हेतु हड़ताल करना बहुत ही कठिन, लगभग असंभव कर दिया गया है। 299 तक के श्रमिक संख्या वाले उद्योगों में नियोक्ताओं को जब चाहें मजदूरों की छंटनी करने, ले-ऑफ, तालाबंदी व कारखाना बंदी करने और महिलाओं को रात्रि पाली में काम पर बुलाने का अधिकार दे दिया गया है। स्थायी किस्म के काम को भी ठेके पर अथवा फिक्स्ड टर्म एम्पलायमेंट के तहत कराया जा रहा है। श्रमिक न्याय पाने के लिए अब सीधे अपनी मर्जी से कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। इसी तरह के अनेक प्रावधान इन लेबर कोड में लाये गए हैं, जिनसे वे भारत के मजदूरों को पूंजीपतियों के गुलाम बनाने पर उतारू हैं।

समालखा : मजदूरों की सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड हरिप्रकाश

इस सभा में जोरदार मांग उठाई गई कि चारों लेबर कोड तुरंत रद्द किये जाएं। रद्द किये गये 29 श्रम कानून बहाल हों, उन्हें संशोधित करके मजदूर हित में समृद्ध किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों- विभागों व संपत्तियों को पूंजीपतियों को देने पर रोक लगायी जाये। न्यूनतम वेतन 26000 रुपये मासिक घोषित किया जाये। पुरानी पेंशन बहाल की जाये, एनपीएस व यूपीएस रद्द किया जाये। बिजली संशोधन बिल 2025 वापस लिया जाये। आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा सहित सभी स्कीम वर्करों व हर तरह के कच्चे, ठेका व आउट सोर्सिंग कर्मियों को पक्का किया जाये। अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाये। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को स्थायी भर्ती करके भरा जाये।

सभा को एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी, एआईकेकेएमएस के नेता कॉमरेड ईश्वर सिंह दहिया, मास्टर बलवीर सिंह, कारखाना मजदूर यूनियन के प्रधान कॉमरेड शेर सिंह, कॉमरेड राजवीर, कॉमरेड अलियास, कॉमरेड राममेहर सिंह आदि ने भी संबोधित किया।

सभा की समाप्ति के बाद विरोध जुलूस निकाला गया और विरोध स्वरूप चार लेबर कोडों की प्रतियां फूंकी गयीं। इस मौके पर एक ज्ञापन/मांगपत्र प्रधानमंत्री, भारत सरकार के नाम उपमंडल अधिकारी (नागरिक), समालखा की मार्फत भिजवाया गया।

प्रदर्शन में दर्जनों उद्योगों के मजदूरों के सैकडों प्रतिनिधि शामिल हुए।

जबरन कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध करने पर किसान नेताओं पर किये गये हमले का एसकेएम ने किया विरोध

अपने 10 दिसंबर को जारी प्रेस बयान में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने हमले की निंदा की, जिंदल-पोस्को प्रतिरोध मंच के बहादुराना संघर्ष की सराहना की, जो आरएसएस द्वारा थोपी जा रही कॉर्पोरेट लूट से मातृभूमि की रक्षा कर रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों की पहचान करने, सख्त कानूनी कार्रवाई करने, राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और लोगों के विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ओडिशा के क्योंझर में एसकेएम के राष्ट्रीय नेता और एआईकेकेएमएस के अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान और अन्य किसान नेताओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। आरएसएस-बीजेपी के गुंडों द्वारा किया गया यह कायराना हमला और अपहरण देशभक्त आंदोलनकारियों को धमकाने की एक घिनौनी चाल है, जबकि सरकार खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश कर रही है।

गुंडे लाठियों और अन्य हथियारों से लैस थे और उन्होंने कॉमरेड सत्यवान सहित सभी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इस दौरान सत्यवान के माथे पर चोट लगी। गुंडों ने नेताओं का अपहरण किया और बाद में उन्हें ओडिशा के क्योंझर जिले के तुरुमुंगा थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उन्हें कई घंटों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। गुंडों ने नेताओं के मोबाइल फोन छीनने की कई कोशिशें कीं, थाने के बाहर भी और अंदर भी। उन्हें व्यावहारिक रूप से किसी से फोन पर बात करने नहीं दिया गया। यह सारी बदसलूकी पुलिस की मौजूदगी में हुई और बाद में कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाया। उसके बाद पुलिस ने कॉमरेड सत्यवान और अन्य नेताओं को रिहा किया।

एसकेएम ने ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरन माझी को पत्र लिखकर सभी दोषियों की पहचान कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और नागरिकों के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है।

यह शर्मनाक घटना 9 दिसंबर 2025 को उस समय हुई, जब कॉमरेड सत्यवान और अन्य साथी क्योंझर जिले के जमुनापोसी गांव से लौट रहे थे, जहां उन्होंने जिंदल-पोस्को प्रतिरोध मंच के बैनर तले संघर्ष कर रहे ग्रामीणों की एक आमसभा को संबोधित किया था। ग्रामीण अपनी उपजाऊ कृषि भूमि को पोस्को-जिंदल समूह द्वारा जबरन छीने जाने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जिंदल परिवार बीजेपी परिवार का हिस्सा है और पोस्को एक कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी है।

दौरे के दौरान ग्रामीणों ने नेताओं से कहा कि यह गांव उनकी पुश्तैनी जमीन है, उनकी जिंदगी, जीविका और पहचान गांव से गहराई से जुड़ी है और किसी भी हालत में वे अपनी जमीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नहीं देंगे। वे अंत तक लड़ने के लिए पूरे दृढ़ संकल्पित हैं।

संघर्षरत ग्रामीणों का मनोबल तोड़ने के लिए पुलिस बल और असामाजिक तत्वों ने मिलकर कई बार ग्रामीणों पर हमले किये हैं। 26 नवंबर की आधी रात को भारी पुलिस बल ने गांवों को घेर लिया और जिंदल-पोस्को प्रतिरोध मंच के सचिव कॉमरेड बेनुधर सरदार और अन्य 5 नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किये। वे अभी जेल में हैं। कॉमरेड सत्यवान और अन्य नेताओं ने ग्रामीणों की सभा में भाग लिया और एसकेएम की ओर से उन्हें समर्थन दिया।

ग्रामीणों को उखाड़ फेंकने में असफल होने और राष्ट्र तथा जनता की संपत्तियों को विदेशी शोषकों और उनके देशी सहयोगियों को बेचने की घिनौनी साजिश के उजागर हो जाने के डर से, आरएसएस ने दिनदहाड़े ऐसा अवैध कृत्य किया। हमारा स्पष्ट मत है कि ये संगठित आपराधिक गतिविधियां किसानों की अनिच्छा के बावजूद उनकी जमीन छीनने का रास्ता साफ करने के लिए की जा रही हैं। यह न केवल लोकतांत्रिक आंदोलन पर, बल्कि गरीब जनता के जीवन पर भी एक घोर हमला है।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) लोकतांत्रिक ताकतों और मेहनतकशों से अपील करता है कि वे आगे आयें और फासीवादी बीजेपी सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गठजोड़ के हमलों को वीरतापूर्वक नाकाम करें।

रांची (झारखण्ड) : उलगुलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समापन समारोह

भुवनेश्वर : ओडिशा के क्योंझर जिले के पाटाना ब्लॉक में जबरन भूमि हड़पने के खिलाफ 8 दिसंबर को एआईकेकेएमएस द्वारा आयोजित जुलूस

एआईडीवाईओ का प्रथम चण्डीगढ़ यूटी सम्मेलन आयोजित

चण्डीगढ़ : क्रांतिकारी युवा संगठन एआईडीवाईओ द्वारा शहीद भगत सिंह भवन, कुम्बड़ा, मोहाली में संगठन का प्रथम चंडीगढ़ यूटी राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में चंडीगढ़ ट्राईसिटी के विभिन्न भागों से आये हुए युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान युवाओं से जुड़े अनेक मुद्दों, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, अपसंस्कृति एवं महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराध आदि पर चर्चा हुई। चर्चा में सभी प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए अपनी-अपनी राय व्यक्त की।

सभा को संबोधित करते हुए एआईडीवाईओ के महासचिव कॉमरेड अमरजीत सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लाखों पदों व परीक्षाओं में हो रही पेपर लीक की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने इसके विरुद्ध जोरदार युवा आंदोलन चलाने की अपील की। साथ ही देश में बढ़ते सांस्कृतिक पतन, नशाखोरी, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता व महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते आपराधिक मामलों के खिलाफ तमाम युवाओं को एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की बात कही।

अंत में कॉमरेड कुलदीप सिंह ने इस सम्मेलन को आयोजित करने पर बधाई देते हुए चंडीगढ़ यूटी की 17 सदस्यीय राज्य कमेटी का प्रस्ताव रखा, जिसका मौजूद प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन किया गया। इसमें कॉमरेड अमित कुमार को अध्यक्ष, कॉमरेड चंदा भारती को उपाध्यक्ष, कॉमरेड अखिलेश कुमार को सचिव एवं कॉमरेड रवि आफताब को कार्यालय सचिव चुना गया।

फीस वृद्धि और नर्सिंग छात्राओं के साथ किये गए दुर्व्यवहार, अभद्रता व जोर-जबरदस्ती की घटना की एआईडीएसओ ने की कड़ी निंदा

रोहतक (हरियाणा):

खुशी नर्सिंग कॉलेज प्रशासन द्वारा फीस वृद्धि और छात्राओं के साथ किये गए दुर्व्यवहार, अभद्रता, जोर-जबरदस्ती की घटना की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) कड़ी निंदा करता है और छात्राओं के आंदोलन का समर्थन करता है।

एआईडीएसओ के प्रदेश सचिव कॉमरेड उमेश मौर्य ने 12 दिसम्बर को जारी एक प्रेस बयान में कहा कि छात्राओं के हॉस्टल में पुरुष वार्डन नियुक्त करना बेहद अनुचित है। पहले से ही भारी फीस वसूलने के बाद भी हॉस्टल फीस बढ़ा दी गई और निम्न गुणवत्ता का खाना परोसा जा रहा है। विरोध करने पर उनको धमकाया जा रहा है और उनके साथ जोर-जबरदस्ती व अभद्रता की जा रही है। कॉलेज की छात्राएं अपनी समस्याओं के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सरकार कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है।

छात्र नेता ने कहा कि यह शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण का अनिवार्य परिणाम है। शिक्षा को मुनाफा कमाने का साधन बना दिया गया है। सरकार शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे ऐसे काम करने वालों को बढ़ावा मिल रहा है।

छात्र संगठन कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार से मांग करता है कि उनकी जायज मांग को अविलंब पूरा किया जाए। दोषियों के खिलाफ कड़ी करवाई की जाए और छात्राओं को न्याय दिया जाये। प्रदेश में शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण पर रोक लगायी जाए। प्रदेश के अन्य कॉलेजों में जहां भी इस तरह की समस्याएं हैं, उनको तुरंत हल किया जाए।

लेबर कोडों के विरोध में रोष प्रदर्शन

मुंबई (महाराष्ट्र) : मजदूर-विरोधी 4 श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के खिलाफ एआईयूटीयूसी, सीटू और कामगार एकता कमेटी की ओर से 16 अक्टूबर को भिवंडी, जिला ठाणे, मुंबई के एमएमआर क्षेत्र में रोष प्रदर्शन किया गया।

जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

रायपुर : प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कॉमरेड विश्वजीत हारोड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) : राज्य की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने 10 दिसंबर को यहां एक दिवसीय प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके पहले पूरे राज्य में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन पत्र पर बीस हजार से अधिक हस्ताक्षर इकट्ठे किये। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया।

इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वे पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे थे : 'बिजली हाफ योजना 400 यूनिट तक लागू करो', 'स्मार्ट मीटर योजना बंद करो', 'पूंजीपतियों के लिए जंगल व खेती की जमीन का जबरन अधिग्रहण बंद करो', 'अदानी के लिए हसदेव जंगल उजाड़ना बंद करो', 'अनियमित व योजना कर्मियों को नियमित करो', 'आंगनबाड़ी कर्मियों एवं मितानिनों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दो', 'सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन 26000 रुपये लागू करो', 'किसानों की सारी उपज लाभकारी समर्थन मूल्य पर खरीदो', 'पूरे राज्य में सरकारी परिवहन व्यवस्था लागू करो', 'महिलाओं पर हो रहे अपराध रोको', 'अवैध घोषित कर गरीब बस्तियों को उजाड़ना बंद करो', 'दस हजार सरकारी स्कूल बंद करना नहीं चलेगा', 'शिक्षकों के हजारों पद समाप्त करना नहीं चलेगा' आदि।

सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड विश्वजीत हारोडे कहा कि छत्तीसगढ़ की आम जनता बिजली बिल वृद्धि, बेरोजगारी और महंगाई सहित कई समस्याओं से ग्रस्त है। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी गई थी, लेकिन जन आंदोलन के दबाव में इसे सिर्फ 200 यूनिट तक चालू किया गया है। इसका फायदा भी जनता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नए स्मार्ट मीटर से बिजली बिल कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। जनता का जीना दुश्वार हो गया है। दूसरी ओर, पूंजीपतियों, विशेष कर अदानी के हित में हसदेव जंगल सहित छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों में किसानों एवं आदिवासियों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। आंदोलन और जनता की आवाज अनसुनी की जा रही है। पूंजीपतियों के हित में एकतरफा कार्रवाई चालू है।

पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड आत्माराम साहू ने कहा कि वर्तमान विष्णु देव साय सरकार केंद्र की भाजपा सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रही है। राज्य के विकास के लिए कोई ठोस योजना पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। धान खरीदी में किसानों की स्थिति खराब है। एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। रोजगार नहीं है। राज्य में न्यूनतम वेतन पूरे देश में सबसे कम है। पलायन जारी है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। स्कूल बंद किये जा रहे हैं और शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अति गंभीर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की आम जनता बहुत परेशान है। ऐसे में जन समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन ही लोगों के लिए एकमात्र रास्ता है।

विधानसभा पर प्रदर्शन

नागपुर (महाराष्ट्र) : 10 दिसंबर को यहां विधानसभा पर एआईयूटीयूसी से संबद्ध जागृती मोलकरीण संघर्ष समिति का मोर्चा हुआ, जिसमें घरेलू महिला मजदूरों की 14 मांगें सरकार के समक्ष रखी गयीं।

94 हजार सरकारी स्कूल बंद करने की नीति के खिलाफ
1 लाख हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा

भोपाल (मध्य प्रदेश) : राज्य के 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की राज्य सरकार की नीति के खिलाफ स्कूल बचाओ संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश के तत्वावधान में मध्य प्रदेश में चलाये गए हस्ताक्षर अभियान के क्रम में 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षरों पर जनमत संग्रह कर प्रदेश के 35 जिलों से हजारों छात्रों और अभिभावकों ने राजधानी के नीलम पार्क में विरोध प्रदर्शन कर सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के आंदोलन का आगाज किया। ज्योतिबा फुले, जिन्होंने हमारे देश में सभी को शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ी और सैकड़ों स्कूल खोले, उनके संघर्ष को याद करते हुए इस प्रदर्शन में राज्य के लाखों छात्रों के भविष्य को बचाने का संकल्प लिया गया।

मुख्य वक्ता कॉमरेड मुदित भटनागर ने कहा कि आंदोलन की तैयारी में मध्य प्रदेश के हर जिले में छात्रों ने अपनी पहल पर शहर से लेकर दूर दराज के गांवों तक जाकर स्कूलों को बंद करने के खिलाफ हस्ताक्षर इकट्ठे किये। इस आंदोलन को छतरपुर, ग्वालियर टीकमगढ़, गुना, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, दतिया, अशोकनगर, भिंड, मंडला, अलीराजपुर, इंदौर, जबलपुर, सागर सहित 35 जिलों में एक-एक जिले में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल सभी जगह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का भरपूर समर्थन एवं सहयोग मिला। भोपाल जिले के 100 से ज्यादा स्कूलों सहित राज्य के 500 से ज्यादा स्कूलों में प्रचार किया गया। छात्रों ने स्कूल-कॉलेजों से 5 रुपये 10 रुपये चंदा इकट्ठा कर आंदोलन को समर्थन दिया। कई जिलों में

लोगों ने स्कूल बचाओ रैलियां आयोजित कीं, जिनमें सैकड़ों छात्र-अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर कई किलोमीटर दूर रैलियों में शामिल हुए। आंदोलन की तैयारी में सैकड़ों स्कूल जर्जर हालत में मिले। कई गांवों के स्कूल बंद मिले, जहां पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अब अंधकार में है।

प्रदेश में 2015-16 में जहां 1 लाख 21 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल थे, वहीं पिछले कुछ सालों में 29,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। इसके चलते प्रदेश में विगत 10 सालों में लगभग 50 लाख छात्र ड्रॉप आउट हो चुके हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बचाने, शिक्षकों की स्थाई भर्ती, जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार और छात्रों की सुरक्षा की मांग उठायी।

उत्तर प्रदेश से आये स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के प्रभारी दिलीप सरवार ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के विभिन्न राज्यों सहित उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूलों को बंद करने की रची गई साजिश के खिलाफ उत्तर प्रदेश के छात्रों व आम लोगों ने जोरदार आंदोलन चलाया और उत्तर प्रदेश के 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद होने से बचाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 ही विकल्प हैं या तो स्कूलों को बंद होने दें और बेहतर भविष्य की कल्पना करना छोड़ दें या इसके खिलाफ संघर्ष कर शिक्षा पाने का हक हासिल करें।

विशिष्ट अतिथि विख्यात साहित्यकार व शिक्षाविद सुरेंद्र रघुवंशी ने आंदोलन के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज की व स्कूल बचाओ-भविष्य बचाओ आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने प्रदेशभर में शिक्षकों की कमी और शिक्षकों पर बढ़ते गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया।

प्रदर्शन में आये विभिन्न जिलों के छात्र प्रतिनिधियों, जो दिन-रात एक कर इस आंदोलन की तैयारी में जुटे रहे, ने बड़े ही मार्मिक ढंग से सरकारी स्कूलों के हालात और चौपट होती शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जतायी। स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अजीत सिंह पंवार ने अंत में आह्वान किया कि शिक्षा ही हमें इंसान बनाती है, इसलिए हमें स्कूल बचाओ-भविष्य बचाओ का नारा लेकर प्रदेश के सभी 55 जिलों के एक-एक गांव-शहर तक पहुंचना होगा और हजारों संघर्ष समितियां बनानी होंगी। छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों को सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी और संकल्प लेना होगा कि हम एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे।

सभा का संचालन संघर्ष समिति की सदस्य श्रुति शिवहरे ने किया।

शिक्षा-विरोधी वीबीएसए/एचईसीआई बिल के खिलाफ प्रेस वार्ता आयोजित

दिल्ली : मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किये गए वीबीएसए/एचईसीआई बिल के खिलाफ 15 दिसंबर को यहां छात्रों, शिक्षकों के संगठनों और सेव एजुकेशन कमेटी की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ की दिल्ली की सचिव कॉमरेड श्रेया ने कहा कि यह बिल शिक्षा-विरोधी है और शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायतता पर हमला है। उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए एनईपी-2020 के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के महत्व पर जोर दिया।

PRGI Regn. No. 43022

दर्शन और विज्ञान....

(पृष्ठ 2 का शेष)

परिवर्तन की ओर ले जाती है। इस परिवर्तन के कारण वस्तु का एक नया अस्तित्व शुरू होता है, जो उसके पिछले अस्तित्व का निषेध करता है। लेकिन परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया यहीं रुक नहीं जाती है, बल्कि जारी रहती है। इस नए अस्तित्व में मात्रात्मक परिवर्तन फिर से शुरू होता है, जो किसी बिंदु पर गुणात्मक परिवर्तन को जन्म देता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर' (प्रकृति की द्वंद्वात्मकता) में इस 'वाइस-वर्सा का उदाहरण दिया है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक गति में बदलना और यांत्रिक गति का फिर से ऊष्मा ऊर्जा में बदलना।

भारत के एक विशिष्ट मार्क्सवादी दार्शनिक शिवदास घोष ने इस अवधारणा को और विकसित किया। उन्होंने दिखाया कि 'मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन' और 'वाइस वर्सा' दोनों किसी वस्तु के परिवर्तन की प्रक्रिया में साथ-साथ और एक-दूसरे के साथ सामंजस्य में काम करते हैं। उनके अनुसार, प्रत्येक मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में असंख्य गुणात्मक परिवर्तन निहित होते हैं। प्रत्येक वस्तु-सत्ता कुछ 'मूलभूत तत्वों' से बनी होती है। जिस प्रकार एक गिलास पानी असंख्य जल कणों से बना होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव किसी विशेष जैविक प्रजाति के 'निर्माण खंड' होते हैं; किसी समाज के 'निर्माण-खंड' व्यक्ति-मनुष्य होते हैं। जब कोई सत्ता छोटे मात्रात्मक परिवर्तनों से गुजरती है, तो उसे बनाने वाले कुछ मूल तत्वों में गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। जब एक गिलास पानी का तापमान बढ़ता है (मात्रात्मक परिवर्तन), तो कुछ जल कण वाष्प में बदल जाते हैं (गुणात्मक परिवर्तन)। जब पूंजीवादी समाज मात्रात्मक परिवर्तन से गुजरता है, तो उस समाज के कुछ व्यक्ति गुणात्मक परिवर्तनों से गुजरकर क्रांतिकारी बन जाते हैं और इस प्रक्रिया में, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था गुणात्मक परिवर्तनों से गुजरती है। इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन एक-दूसरे से अविभाज्य हैं और दोनों प्रक्रियाएं एक के बाद दूसरी नहीं, बल्कि निरंतर एक साथ घटित होती रहती हैं।

विज्ञान में दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं संभाव्यता और निर्धारणवाद (Probability and Determinism)। कई लोग सोचते हैं कि ये परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं, अगर कोई चीज निश्चयात्मक है, तो संभाव्यता की कोई भूमिका नहीं होती और अगर कोई चीज संभाव्य है, तो वह निर्धारणवाद के नियमों का उल्लंघन करती है। इस दृष्टिकोण ने क्वांटम यांत्रिकी सहित आधुनिक विज्ञान की कुछ खोजों को लेकर बहुत भ्रम उत्पन्न किया।

क्वांटम जगत में कणों की गति संभाव्यता द्वारा निर्धारित होती है। हाइजेनबर्ग का अनिर्धारणता सिद्धांत कहता है कि किसी छोटे कण की स्थिति और संवेग (द्रव्यमान गुना वेग) को एक ही समय में पूरी सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। किसी कण की स्थिति जितनी अधिक सटीकता से निर्धारित की जाती है, उसका संवेग उतना ही कम सटीकता से निर्धारित होता है और अगर संवेग का सटीक निर्धारण किया जाता है, तो उसकी स्थिति उतनी ही कम सटीकता से निर्धारित होती है। यह एक प्राकृतिक नियम है—अगर किसी कण का एक निश्चित मान का संवेग है, तो उसकी स्थिति का कभी भी एक निर्धारित मान नहीं होता। उसकी स्थिति कहीं भी (निश्चित रूप से एक सीमा के भीतर) हो सकती है और विभिन्न स्थानों पर उसके होने की संभावनाएं गणितीय रूप से निर्धारित की जा सकती हैं।

इसकी कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने इस तरह व्याख्या की कि क्वांटम जगत में कार्य-कारण (Causality) और निर्धारणवाद (Determinism) काम नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म कणों की गति यानी संवेग अराजक या उच्छृंखल हो और किसी नियम का पालन नहीं करता हो। सूक्ष्म कणों की गति यानी संवेग पूरी तरह से नियमबद्ध होता है, जिसे संभावता का नियम निर्धारित करता है। क्वांटम सिद्धांत में संभावनाएं भी निर्धारणात्मक निर्धारणवाद पर आधारित एक प्रक्रियागत ढंग से और नियम-शासित प्रक्रिया के जरिये निर्धारित होती हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि क्वांटम जगत में संभाव्यता के नियमों का संचालन निर्धारणवाद को असत्य सिद्ध करता है। शिवदास घोष ने कहा था, 'निर्धारणवाद की प्रचलित अवधारणा यांत्रिकता से ग्रस्त है। अगर आप गौर से देखेंगे, तो समझेंगे कि निर्धारणवाद की यह अवधारणा दरअसल पूर्वनिर्धारणवाद से आच्छादित है। इसी वजह से इसने अनेक लोगों को निर्धारणवाद को दरअसल भाग्यवाद या नियतिवाद समझने की ओर प्रवृत्त कर दिया है। इसलिए, मेरा मानना है कि यह सच नहीं है कि आधुनिक विज्ञान में संभाव्यता की अवधारणा—जैसे 'अनिर्धारणता के सिद्धांत' के मामले में या सूक्ष्म कणों से संबंधित अनेक अन्य मामलों में—ने निर्धारणवाद को कमजोर किया है या कार्य-कारणता खत्म कर दिया है। अगर सही ढंग से समझा जाए, तो दिखेगा कि संभाव्यता के सिद्धांत ने दरअसल निर्धारणवाद को पूर्वनिर्धारणवाद की भ्रांति से मुक्त कर उसे एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।' एंगेल्स ने भी अपनी पुस्तक 'डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर' ('प्रकृति की द्वंद्वात्मकता') के 'संयोग और आवश्यकता' नामक अध्याय में यांत्रिक भौतिकवादी दृष्टिकोण में व्याप्त पूर्व-निर्धारणवाद यानी भाग्यवाद के रुझान की ओर इशारा किया है।

एक उदाहरण: आधुनिक आनुवंशिकी के प्रकाश में डार्विन का 'क्रमविकास का सिद्धांत'

विज्ञान एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के जरिये कैसे काम करता है—यह समझने के लिए, आइए, जैविक विकास की प्रक्रिया पर विचार करें, जिसे डार्विन ने प्रतिपादित किया था और जो आनुवंशिकी के विकास के साथ विकसित हुई है। इस मामले के दो पहलू हैं—व्यक्ति विशेष जीव और उसकी पूरी प्रजाति। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के साथ हर पल द्वंद्व-संघर्ष में रहता है। किसी भी जीव की शारीरिक संरचना निश्चित रूप से मुख्यत: उसके 'आनुवंशिक कोड' द्वारा और भोजन की आपूर्ति जैसे अन्य पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। विस्तार में जाये बिना संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कोई भ्रूण घोड़ा बनेगा या मछली, यह उस जीव की शारीरिक संरचना के बारे में जानकारी से निर्धारित होता है, जो सबसे पहली कोशिका में निहित होती है। यह जानकारी डीएनए नामक एक विशेष अणु में पायी जाती है, जो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक का हिस्सा होता है। इस डीएनए के विभिन्न भाग, मूल सूचना-वाहक भाग, 'जीन' कहलाते हैं। इस जानकारी का स्रोत उस जीव के माता और पिता की प्रजनन कोशिकाओं के डीएनए अणु होते हैं।

किसी विशेष प्रजाति में शुमार प्रत्येक जीव का डीएनए बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। मूलत: इनमें एक समानता होती है—उदाहरण के लिए, दो कौओं या दो गधों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जिनसे कौओं और गधों को हम वर्गीकृत कर पाते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतर भी होते हैं, जिन्हें आधुनिक उपकरणों से पहचाना जा सकता है। यही वे सूक्ष्म अंतर यानी एक ही प्रजाति के एक जीव की शारीरिक संरचना में दूसरे जीव से भिन्नताएं या विविधताएं हैं, जिनका डार्विन ने जिक्र किया है। प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के दौरान जब कुछ असंगति हो जाती है, तो विविधताएं लिये हुए नई किस्में यानी प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। 'उत्परिवर्तन' नामक यह घटना जैविक जगत में निरंतर होती रहती है।

किसी भी प्रजाति का प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के साथ हर पल द्वंद्व-संघर्ष में रहता है और उनके आनुवंशिक कोड में सूक्ष्म भिन्नताओं से उत्पन्न विविधताओं के कारण पर्यावरण के साथ अनुकूलन या अनुकूलन करने की उनकी क्षमता समान नहीं होती है। इसलिए जीवित रहने की संभावनाएं समान नहीं होतीं। जो जीव वयस्क होने तक जीवित रहते हैं, वे अपना आनुवंशिक कोड अगली पीढ़ी की संतानों तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार, प्राकृतिक चयन कुछ जीनों को विशेष लाभ पहुंचाता है और कुछ जीनों को हटा देता है, जो जीव के अस्तित्व के लिए प्रतिकूल होते हैं। यही प्रक्रिया प्रजाति की जनसंख्या में धीरे-धीरे और मात्रात्मक परिवर्तन का कारण बनती है। आधुनिक शब्दों में, प्रतिस्पर्धी जीनों की सापेक्ष आवृत्ति समय के साथ बदलती रहती है।

जब उत्परिवर्तन के जरिये कोई नया जीन उत्पन्न होता है, जो मेजबान जीव की शारीरिक संरचना या व्यवहार में बड़ा परिवर्तन लाता है, तो उस प्रजाति में गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। उत्परिवर्तन सबसे पहले किसी विशेष जीव में होता है। अगर यह उत्परिवर्तन उसके अस्तित्व के लिए लाभदायक होता है, तो वह विशेष जीव के वयस्क होने पर नए और उत्परिवर्तित जीन को अपनी अगली पीढ़ी की संतानों में स्थानांतरित करने की संभावना अधिक होती है। अगर उस प्रजाति के उन जीवों, जिनमें वह उत्परिवर्तित जीन होता है, के जीवित रहने की संभावना इस जीन के गैर वाहक जीवों की तुलना में अधिक होती है, तो वह उत्परिवर्तित जीन पूरी प्रजाति में तेजी से फैल जाता है। केवल कुछ ही पीढ़ियों में, वह उत्परिवर्तन उस प्रजाति के लगभग सभी जीवों में मौजूद हो सकता है। फिर, अगर किसी पूरी प्रजाति को देखें, तो पायेंगे कि उसमें नई विशेषताएं उभरी हैं और वह गुणात्मक रूप से बदलकर एक नई प्रजाति बन चुकी है। इस प्रकार, विभिन्न जीनों के अनुपात में मात्रात्मक परिवर्तन पूरी प्रजाति में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं।

हालांकि अगर हम किसी प्रजाति के प्रत्येक जीव की जांच करें, तो हम पायेंगे कि पूरी प्रजाति के गुणात्मक रूप से बदलने से बहुत पहले, उसके सदस्य कुछ जीव गुणात्मक रूप से बदल जाते हैं। जिन विशेष जीवों को नए जीन विरासत में मिले हैं, उन जीवों में हुआ गुणात्मक परिवर्तन पूरी प्रजाति के संदर्भ में मात्रात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। 'गुणात्मक से मात्रात्मक परिवर्तन' वाला पक्ष वास्तव में इसी प्रकार कार्य करता है। जैविक क्रमविकास की प्रक्रिया की आधुनिक समझ ने स्पष्ट कर दिया है कि संभाव्यता और कार्य-कारणता के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। आनुवंशिकी के शुरुआती दिनों में कुछ कम्युनिस्टों को इस मामले की स्पष्ट समझ के अभाव ने इसका विरोध करने की ओर प्रवृत्त किया था। अब हम समझते हैं कि हालांकि यादृच्छिक (बेतरतीब) प्रकृति के उत्परिवर्तनों के जरिये नई विविधताएं लगातार उभर रही हैं, फिर भी ये विविधताएं बरकरार रहेंगी या नहीं और आगे चलकर प्रजातियों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करेंगी या नहीं, यह सब पूरी तरह कार्य-कारण के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि प्राकृतिक चयन प्रत्येक विशिष्ट विविधता को बरकारार रहने की अलग संभावनाएं प्रदान करता है।

आधुनिक आनुवंशिकी के विकास ने लंबे अर्से से अनसुलझी कई गुत्थियों को सुलझाना संभव बना दिया है। इसने इस प्रतिपादन को पुन: स्थापित किया है कि 'किसी भी परिवर्तन का मूल कारण आंतरिक होता है'। इसने बाह्य द्वंद्व-संघर्ष की भूमिका को फिर नये सिरे से परिभाषित किया है। डार्विन के सिद्धांत का कार्य-कारण संबंध, जो आनुवंशिकी के शुरुआती दिनों में अस्पष्ट था, अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है।

निष्कर्ष

मुख्य बात यह है कि विज्ञान आज भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद द्वारा दिखायी गयी दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, भले ही वैज्ञानिक स्वयं इससे वाकिफ न हों। इसलिए इस बारे में जागरूकता बढ़ाना हमारा कर्तव्य है ताकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को वैज्ञानिक विमर्श के केंद्र में पुन: वापस लाया जा सके।

बाद के मार्क्सवादी दार्शनिकों द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणाओं को और विकसित व समृद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि ज्ञान एवं कार्यप्रणाली का एक सुसंगत ढांचा निर्मित किया जा सके। अगर हम इस बात से आश्वस्त हैं कि इस दार्शनिक नजरिये की मदद से हम विज्ञान के विभिन्न विकासक्रमों और आधुनिक अवधारणाओं को समझ सकेंगे, तो हमें उत्तर-आधुनिकतावाद, अनुभवजन्य एकेश्वरवाद, नव भौतिकवाद, उत्तर-मानवतावाद आदि विभिन्न ''संशोधनवादी'' प्रवृत्तियों को परास्त करना चाहिए।

साथ ही, दुनियाभर के सभी मार्क्सवादियों को आधुनिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हो रहे वैचारिक प्रगति को भली-भांति जानना-समझना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर विकसित हुआ है। इसलिए वर्तमान युग में जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति होगी, उसके अनुरूप इस दर्शन को विकसित और समृद्ध करने के प्रयास भी जारी रहने चाहिए। ●

अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा की गई वेनेजुएला की नाकाबंदी की
एसयूसीआई (सी) ने की निंदा

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 19 दिसम्बर को जारी प्रेस बयान में कहा:

"जंगखोर अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए एक छोटे से देश वेनेजुएला को सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से पूरी तरह घेर लिया है, उसकी आजादी व संप्रभुता को खतरा पैदा कर दिया है और उसके तेल निर्यात को रोक दिया है, जिस पर देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर करती है। उनका मकसद राष्ट्रपति मादुरो को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना है ताकि वहां अमेरिकी साम्राज्यवादियों की कठपुतली सरकार कायम की जा सके। हम उनके इस मौजूदा मंसूबे का कड़ा विरोध करते हैं और सभी साम्राज्यवाद-विरोधी शांति-पसंद लोगों से इस घिनौनी साजिश के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की अपील करते हैं।"

भारत के नवजागरण के मूल्यों को नकारती है आरएसएस की राजनीति

(पृष्ठ 1 का शेष)

टैगोर द्वारा रचित 'जन गण मन' को राष्ट्रीय गान के रूप में चुना गया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहसपूर्वक इसे गाया, जब आरएसएस-हिंदू महासभा की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई उपस्थिति नहीं थी।

इसके विपरीत, आरएसएस के विचारक स्पष्ट रूप से मानते थे कि ब्रिटिश-विरोधी आजादी आंदोलन प्रकृति में प्रतिक्रियावादी था, क्योंकि यह 'क्षेत्रीय राष्ट्रवाद' की बात कर रहा था, न कि 'हिंदू राष्ट्रवाद' की।

एक लेख में भाजपा और आरएसएस नेता राम माधव ने कहा कि वंदे मातरम के केवल दो छंदों को रखने के फैसले के पीछे कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण था। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नेताओं पर 1937 के चुनावों में मुस्लिम वोट पाने के लिए अवसरवादी रूप से अपना रुख बदलने का सीधा आरोप लगाया। हां, यह सच है कि वंदे मातरम के सिर्फ दो पद ही 1937 में कांग्रेस द्वारा अपनाये गए थे, जो उस समय आजादी चाहने वाली सभी ताकतों का एक मंच था। लेकिन इसका एक पक्का कारण था। जब 19वीं सदी में भारतीय नवजागरण आंदोलन उभरकर आया, तो बुर्जुआ मानवतावाद या बुर्जुआ जनवादी क्रांति के दर्शन में पश्चिमी नवजागरण जैसा वह अटूट युवा जोश नहीं बचा था, क्योंकि पूंजीवाद न सिर्फ एक विश्व व्यवस्था के रूप में पहले ही प्रतिक्रियावादी ताकत में तब्दील हो चुका था, बल्कि इसने सदियों पुराने, दकियानूसी सामंती मूल्यों, रीति-रिवाजों, धार्मिक अंधविश्वासों और निरंकुशता के खिलाफ अपनी अटूट लड़ाई को छोड़ देना शुरू कर दिया था।

इसलिए अपनी शुरुआत से ही, भारतीय नवजागरण अंदर से कुछ हद तक कमजोर था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक अपवाद थे और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी विचारों को दृढ़ता से कायम रखा, जो किसी भी अलौकिक सत्ता और इसलिए धार्मिक संरक्षण को अस्वीकार करने पर आधारित है। आध्यात्मिकता के साथ इस समझौते का असर साहित्यिक रचनाओं के क्षेत्र में भी साफ दिखाई दे रहा था।

बंकिमचंद्र आजादी की लड़ाई की इस समझौतावादी धारा के दायरे में थे और इसलिए धार्मिक पुनरुत्थानवादी विचारों के पुनर्जन्म के केंद्र में थे, इस तथ्य के बावजूद कि वे देश को विदेशी शासन से आजाद कराना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के तहत, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की इच्छा अधूरी रह गई, बल्कि उसे कुचल दिया गया। इसलिए खासकर शिक्षित वर्ग में, भारतीयों को शासक अंग्रेजों से मिली व्यक्तिगत गरिमा के अपमान को लेकर असंतोष बढ़ रहा था।

भारतीय राष्ट्र की अवधारणा भारतीय जनता की वैध आकांक्षा के इस अपमान की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी। हालांकि, इस अपमान की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक पुनरुत्थान और परंपरावाद के रूप में हुई। देशवासियों की इस आकांक्षा को व्यक्त करने के लिए कि वे विदेशी कब्जे के जाल को तोड़कर एक सम्मानित राष्ट्र के रूप में उभरें, बंकिमचंद्र ने हिंदू परंपरावाद की ओर देखा। 'आनंदमठ' इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया था। इस दृष्टिकोण से, यह कहा जा सकता है कि यह उपन्यास इस धरती पर राष्ट्रवाद का पहला जोश था। इसकी कहानी 1772-73 के आसपास वॉरेन हेस्टिंग्स के समय उत्तरी बंगाल में हुए संन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। असल में, यह कहानी लाखों देशवासियों के दिलों में आजादी के लिए जोश भरने का एक बहाना थी।

बंकिमचंद्र चटर्जी रवींद्रनाथ टैगोर राममोहन राय

सिर्फ दो छंद ही क्यों रखे गए?

लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आनंदमठ, जिसने कई देशभक्त दिलों में आग सुलगा दी थी, एक हिंदू पुनरुत्थानवादी रूपक पर आधारित था, जिसमें भारत एक साझी नागरिक मातृभूमि के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य मां-देवी के रूप में दिखाई देता है, जिसकी पूजा की जानी है। दुर्गा की छवि, तपस्वी योद्धा भिक्षु और हिंदू वर्चस्व की पुकार हल्के पृष्ठभूमि के भाव नहीं हैं; वे वैचारिक रीढ़ हैं। वंदे मातरम गीत पहले दो छंदों में प्रचुर, शांत भूमि का आह्वान करते हुए कोमल, मधुर संस्कृत शब्दों का उपयोग करते हुए धीरे और कोमलता से शुरू होता है। हालांकि, जल्द ही यह तलवारों की खड़खड़ाहट में, दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए बुलंद की गई गरजती आवाजों में बदल जाता है। भूमि दानवों का संहार करने वाली देवी में बदल जाती है, जिसके दस हाथों में घातक हथियार हैं।

इसलिए, रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने खुद 1896 में अपनी किशोरावस्था में यह गीत गाया था, बाद में महसूस किया कि 'वंदे मातरम' में ''तंग ही दुर्गादशप्रहरणधारिणी'' (एक संस्कृत श्लोक, जिसका अर्थ है 'हे दुर्गा, दस हाथों में दस अलग-अलग हथियार धारण करने वाली') शब्द, हालांकि हिंदू धर्म की देवी दुर्गा को मातृभूमि की देवी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए थे, एक देवी, जिसे बंकिम ने खुद गढ़ा था, तुरंत हिंदू देवताओं में एक केंद्रीय स्थान पर पहुंच गए और इसलिए मुस्लिम समुदाय को जगाने में बाधा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं को लिखा: ''मैं खुले तौर पर स्वीकार करता हूं कि बंकिम का पूरा 'वंदे मातरम' अपने संदर्भ के साथ मिलकर इस तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है, जो मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन एक राष्ट्रीय गीत, जो इससे लिया गया है और जो सहज रूप से मूल कविता के पहले दो छंदों तक ही सीमित हो गया है, हमें हर बार पूरे गीत की याद दिलाने की जरूरत नहीं है और न ही उस कहानी की, जिससे यह संयोगवश जुड़ा हुआ था।'' (अमृत बाजार पत्रिका 02-11-1937) रवींद्रनाथ ने देशभक्ति की भावना और भक्ति आदेश के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया। इसलिए, उन्होंने कहा कि "वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं हो सकता, इसके शब्द हिंदू प्रतीकों से भरे हुए हैं, जो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। कोई भी राष्ट्र किसी खास धार्मिक समुदाय का नहीं होता।" 1937 की वर्किंग कमेटी के बयान का टेक्स्ट साफ तौर पर टैगोर के तर्क को दिखाता है। रवींद्रनाथ ने अपने उपन्यास 'घरे बाइरे' (1915) में आनंदमठ की सांप्रदायिक संभावना को भी रेखांकित किया था। उन्होंने अपने गीत "एक सूत्रे बाँधियाछि सहस्रति मन, एक कार्ये सौंपियाछि सहस्र जीवन, वंदे मातरम" (हमने हजार दिमागों को एक धागे में बांध दिया है; हमने हजार जिंदगियों को एक काम के लिए समर्पित कर दिया है। .... वंदे मातरम) में सभी भारतीयों को जोड़ने वाले सूत्र के रूप में 'वंदे मातरम' के सार को बनाये रखने की भी कोशिश की।

इसके अलावा, बंकिमचंद्र ने खुद अपने आखिरी उपन्यास सीताराम में, एक हिंदू राज्य की कल्पना की थी, जिसकी स्थापना एक वीर और आदर्शवादी राजा ने की थी, जो अपने मुस्लिम विरोधियों को हराता है। हालांकि वह उन सभी बुराइयों का प्रतीक बन गया और यहां तक कि उनसे भी आगे निकल गया, जो आमतौर पर मुसलमानों से जुड़ी होती हैं। उसके हिंदू साथियों ने उसे छोड़ दिया और आखिर में एक नेक दिल फकीर ने दुख के साथ यह निष्कर्ष निकाला कि अब हिंदू राज्य में रहना संभव नहीं था। इसलिए आरएसएस नेता का यह दावा कि ''सिर्फ दो पदों को बनाये रखने के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरणा था'' इतिहास का मजाक है।

भारत में किसने बोये विभाजन के बीज?

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, ''वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोये।'' यह सच है, इसमें कोई शक नहीं कि 1937 में 'वंदे मातरम' के सिर्फ दो पद ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाये गए थे। लेकिन यह हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासकों को पांच दया याचिकाएं भेजी थीं, अपनी उम्र कैद की सजा कम करने के लिए बहुत विनम्रता से भीख मांगी थी और ब्रिटिश सरकार की किसी भी सेवा के लिए खुद को स्वयंसेवक के तौर पर पेश किया था, उन्होंने न सिर्फ 'हिंदुत्व' शब्द गढ़ा था।...यह वह अवधारणा है, जो आरएसएस-बीजेपी की वैचारिक नींव रखती है, बल्कि वे 1923 में ही द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक भी थे (अपनी किताब 'एसेंसियल्स ऑफ हिन्दुइज्म' में) जिसे हिंदू महासभा ने 1937 में अपने सम्मेलन में स्वीकार किया था और फिर 1939 में मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था। एक और हिंदू महासभाई नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अविभाजित बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलायी थी और जिनका प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथियों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है, ने 1947 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा था, यह तर्क देते हुए कि बंगाल का बंटवारा होना चाहिए, भले ही भारत का न हो। संयोग से, उन्होंने 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर को भी लिखा था, उन्हें सलाह देते हुए कि 'भारत छोड़ो' आंदोलन को कैसे कुचला जाए। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि 'वंदे मातरम' के शुरुआती दो छंद रखने से देश के बंटवारे के बीज बोये गये?

आरएसएस-बीजेपी द्वारा 'वंदे मातरम' की यह पूजा क्यों?

सच तो यह है कि आरएसएस और बीजेपी ने अपनी शाखाओं या दफ्तरों में कभी 'वंदे मातरम' या 'जन गण मन' नहीं गाया। इसके बजाय, वे 'नमस्ते सदा वत्सले' गाते थे, जो उनके कट्टर सांप्रदायिक हिंदुत्व के सिद्धांत की महिमा का गान करता है। इसलिए आरएसएस-बीजेपी-संघ परिवार की ओर वंदे मातरम के प्रति यह अचानक उमड़ा हुआ समर्पण बिना किसी मकसद के नहीं है। उनके लिए, 'वंदे मातरम' को सिर्फ साम्राज्यवाद-विरोधी आजादी आंदोलन के ताने-बाने का एक हिस्सा नहीं माना जाता। इसे सांप्रदायिक हिंदुत्व के प्रति वफादारी के प्रतीक के रूप में फिर से कोड किया गया है। इसीलिए वे गाने के सभी छंदों को गाने की वकालत कर रहे हैं। गाने को भव्य कार्यक्रमों के साथ मनाने का हालिया बीजेपी का फैसला धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं के मेल को तेज करने और इस उत्पाद को असली देशभक्ति के रूप में परिभाषित करने के मकसद से है।

इस तरह, यह गाना काफी सटीक रूप से संघ परिवार के हिंदुत्व एजेंडे को दर्शाता है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने और हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए धार्मिक आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। जो कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई का गाना था, उसे कट्टर सांप्रदायिक हिंदुत्व के नैतिक निगरानी उपकरण में बदल दिया गया है और नकली देशभक्ति या नकली राष्ट्रवाद में शामिल किया गया है। लेकिन एक बात साफ है। सही सोचने वाले हिंदू इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

बीजेपी द्वारा रवींद्र संगीत पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा

इसके साथ ही, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जैसे बीजेपी नेताओं ने रवींद्रनाथ टैगोर के एक बहुत मशहूर देशभक्ति गीत पर प्रतिबंध लगाने की खुली घोषणा की है। उनका बहाना यह है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना देशद्रोह है, क्योंकि यह बांग्लादेश के कुछ नेताओं के इस दावे का समर्थन करने जैसा है कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पड़ोसी देश का हिस्सा था। वाकई अविश्वसनीय!

इस गाने की रचना के पीछे है एक गौरवशाली इतिहास

जब भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में तत्कालीन अविभाजित बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था, तो इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और उभरते स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिला। उस समय, रवींद्रनाथ ने एक गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, आमी तोमाये भालोबासी (मेरे सोने जैसे बेशकीमती बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूं)। यह गाना हर किसी की जुबान पर था। हालांकि यह बंगाल के विभाजन के संदर्भ में लिखा गया था, लेकिन इसमें राष्ट्रवादी भावना और ब्रिटिश साम्राज्यवादी उत्पीड़कों के खिलाफ गुस्से की अभिव्यक्ति थी। बाद में, विभाजन के बाद, जब पाकिस्तानी सरकार ने उर्दू को एकमात्र राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की अधिकांश आबादी बांग्ला बोलती थी, तो एक बड़ा विरोध आंदोलन शुरू हो गया। 21 फरवरी 1952 को छात्रों और मजदूरों ने ढाका में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन पर गोलियां चलायीं, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए। लेकिन आंदोलन को कोई झटका नहीं लगा, बल्कि यह और तेज हो गया। आखिरकार, पाकिस्तानी शासकों को झुकना पड़ा और 1956 में बांग्ला को पूर्वी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। भाषा आंदोलन एक विशिष्ट बंगाली पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया,

(शेष पृष्ठ 8 पर)

PRGI Regn. No. 43022

वंदे मातरम...

(पृष्ठ 7 का शेष)

अगर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के बीच एक तरह की राष्ट्रवादी भावना नहीं तो, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए व्यापक संघर्ष का अग्रदूत बना, जो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और एक नए संप्रभु पूंजीवादी राज्य के रूप में बांग्लादेश के निर्माण में परिणत हुआ। इसी समय रवींद्र संगीत 'आमार सोनार बांग्ला' को बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। यह गाना भारत और बांग्लादेश दोनों जगह भावनाओं के साथ गाया जाता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार के दौरान बंगालियों की भावनाओं को भुनाने के लिए इस गाने की शुरुआती पंक्तियों को बांग्ला में बड़े प्रयास से बोला था।

लेकिन अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाये जाने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बाद भाजपा-नीत भारत ने हसीना को शरण दी है और बांग्लादेश सरकार के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत में हिंदू कट्टरपंथ के प्रभुत्व की प्रतिक्रिया के रूप में बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ के फिर से उभरने के साथ, भारत सरकार यूनुस सरकार पर इस्लामी कट्टरपंथियों के साथ मिलीभगत करने और वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और हत्याओं को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। इसलिए एक सुविधाजनक निष्कर्ष निकालते हुए आरएसएस-भाजपा अपनी हिंदुत्व विचारधारा और मुस्लिम-विरोधी बयानबाजी के अनुरूप, बांग्लादेश के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर रहे हैं। यही वह तर्क है, जो बीजेपी नेता रवींद्र संगीत 'आमार सोनार बांग्ला' पर प्रतिबंध लगाने के अपने रुख के समर्थन में दे रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय लोग इसे स्वीकार करेंगे?

ब्रिटिश शासकों का एजेंट करार देते हुए बीजेपी नेता ने की राममोहन राय की निंदा

रवींद्र संगीत पर रोक लगाने के साथ-साथ, बीजेपी ने अब भारतीय नवजागरण के दिग्गजों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता इंदर सिंह परमार ने टिप्पणी की कि राजा राम मोहन राय एक 'ब्रिटिश एजेंट' थे, जिन्होंने 'धार्मिक धर्मांतरण का एक कुचक्र' रचना शुरू किया था। उन्होंने दावा किया कि अंग्रेजों ने ऐसे कई लोगों को 'नकली समाज सुधारकों' के रूप में पेश किया था और उन लोगों को बढ़ावा दिया था, जिन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। लेकिन फिर एक महान व्यक्तित्व के बारे में ऐसी गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बात पर जन आक्रोश को देखते हुए, जिन्हें सभी लोग भारत के सुदूर अतीत से उसके अनिश्चित भविष्य तक ले जाने वाले एक जीवित पुल के रूप में पूजते हैं और वह पुल, जिसने सामंती रूढ़िवादिता और आधुनिक मानवता, दकियानूसी रीति-रिवाजों और प्रगति के रास्ते के बीच की खाई को पाटा, भाजपाई मंत्री ने पलटी मारी और माफी मांगी, जिसे उन्होंने अपनी बात बचाने के लिए, 'जुबान फिसलना' कहा। ऐसा जुबान फिसलना पहले कभी नहीं देखा गया जब जुबान से पूरा वाक्य निकल गया हो।

दरअसल, आरएसएस-बीजेपी, जो 'हिंदू राष्ट्र' की वैधता की वकालत करते हैं, भारतीय नवजागरण आंदोलन की लहर का विरोध करते रहे हैं, जिसने धार्मिक बंधन, अज्ञानता, अंधविश्वासी रीति-रिवाजों और प्रथाओं की सदियों पुरानी जड़ता को तोड़ने की कोशिश की और लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता पर आधारित आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज के आगमन की घोषणा की। क्योंकि नवजागरण के विचार उन धार्मिक नियमों, कट्टरवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, जिनका आरएसएस-बीजेपी समर्थन करते हैं। राजा राममोहन राय ने कोलकाता में सरकारी संस्कृत कॉलेज खोलने का विरोध किया था। उन्होंने इसके बजाय आधुनिक विषयों के अध्ययन के लिए एक कॉलेज (अब प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता) स्थापित करने की पहल की थी ताकि शूद्रों को हिंदू कट्टरपंथियों के चंगुल से आजाद कराया जा सके। वह सबसे अमानवीय सतीदाह प्रथा (एक हिंदू अनुष्ठान, जिसमें एक विधवा अपने मृत पति की चिता पर खुद को जला लेती है) को खत्म करने में भी सफल रहे। स्वाभाविक रूप से उन्हें हिंदुत्व समर्थकों की नापसंदगी का सामना करना पड़ता है। तो यह जानबूझकर की गई 'जुबान फिसलने' वाली बात थी। असल में, आरएसएस-भाजपा एक ऐसे मिशन पर हैं, जो सामाजिक पतन का रास्ता साफ करता है, जिसके लिए भारतीय नवजागरण के दिग्गजों को बदनाम करना, उनके योगदान को कमतर आंकना, इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सच्चाई को छिपाना, लोगों की सोचने-समझने की प्रक्रिया को पीछे ले जाना और साथ ही अंधविश्वास, कट्टरता, फूट, अतार्किकता और ऐसी दूसरी बुराइयों को बढ़ावा देना जरूरी है। यह पूंजीपति वर्ग की वह साजिश है, जो इस दमन-उत्पीड़न के प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी शासन को बनाये रखने के लिए है। आरएसएस-भाजपा, जो सत्तारूढ़ भारतीय पूंजीपति वर्ग के भरोसेमंद सेवक हैं, इसे अपने तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

●○●

शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक एकल इकाई के गठन का एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने किया कड़ा विरोध

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 16 दिसम्बर को जारी प्रेस बयान में कहा:

"हम भाजपा-नीत केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए एक एकल छाता नियामक बनाने के लिए संसद में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पेश करने का कड़ा विरोध करते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीए) जैसी मौजूदा संस्थाओं को मिलाकर उनकी जगह लेगा। यह देश में अभी भी बची हुई थोड़ी-बहुत अकादमिक स्वायत्तता को समाप्त करने का एक घिनौना षड्यंत्र है, जिससे शिक्षा पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाएगा।

हम सभी शिक्षकों, छात्रों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और शिक्षा-प्रेमियों को इस घातक कदम के खिलाफ विरोध की संयुक्त आवाज बुलंद करनी चाहिए और एकजुट आंदोलन के दबाव में सरकार को इस फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहिए।"

नवादा में हुई मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिहार शरीफ, नालंदा में विरोध प्रदर्शन

बिहार शरीफ, नालंदा (बिहार) : नवादा में हुई मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, सीपीआई (एम) और इंसाफ मंच के संयुक्त तत्वावधान में 16 दिसंबर को बिहार शरीफ, नालंदा में हॉस्पीटल मोड़ पर प्रतिवाद मार्च व धरना-प्रदर्शन किया गया।

विदित हो कि नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में 5 दिसंबर 2025 को मुस्लिम कपड़ा फेरीवाले मोहम्मद अतहर हुसैन की बर्बरता से मॉब लिंचिंग कर दी गयी। अतहर हुसैन को केवल मुस्लिम होने के संदेह में घेरकर अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, गर्म औजार से दागा गया, उनके कान काटे गए, उनकी उंगली तोड़ी गई और उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला गया। उन्हें अधमरी हालत में छोड़ने के बाद उल्टे उनके खिलाफ ही चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस, जिला प्रशासन और इलाज में लापरवाही के कारण 12 दिसम्बर को अतहर हुसैन की जान चली गई।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि यह घटना बिहार में कानून के शासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह घटना बिहार में भाजपा द्वारा सांप्रदायिक हिंसा के लगातार बनाये जा रहे माहौल का जीता जागता उदाहरण है। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कार्यभार संभालने के बाद बिहार में मॉब हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई बढ़ी है।

अपने संबोधन में वक्ताओं ने मांग की कि अतहर हुसैन के हत्यारे को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दी जाए। अतहर हुसैन पर फर्जी मुकदमा करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, गृह मंत्री सम्राट चौधरी कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सार्वजनिक बयान दें, सत्ता संरक्षित सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगायी जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए व न्याय दिया जाए। पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये दिये जाएं।

धरना-प्रदर्शन को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड सूर्यकर जितेन्द्र, कॉमरेड आर के पी सिंह, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड सुरेंद्र राम, पाल बिहारी लाल, इंसाफ मंच के जिला संयोजक सरफराज अहमद खां, अधिवक्ता ब्रह्मदेव प्रसाद बिंद तथा सीपीआई (एम) के महेन्द्र प्रसाद, विनोद रजक आदि ने सम्बोधित किया।

ग्राम जन कल्याण विधेयक को तत्काल वापस ले सरकार —एआईकेकेएमएस

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने 16 दिसंबर को निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया:

''हम केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा की जगह विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 (वीबी-जीरामजी विधेयक) लाने के घृणित प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य है: पहला, मनरेगा और इसकी वैधानिक गारंटी को निरस्त करना और इसके स्थान पर केंद्र सरकार की ऐसी योजना लाना, जो ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार की कोई गारंटी नहीं देती। दूसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भूमिका को नकारते हुए सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार देना। तीसरा, केंद्र सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी (जो पहले 100 प्रतिशत थी) को घटाकर 60 प्रतिशत करना और इसका 40 प्रतिशत तक बोझ राज्य सरकारों पर स्थानांतरित करना। चौथा, जॉब कार्ड के तर्कसंगतीकरण की घोषणा से काम के अधिकार का हनन होता है। जबकि ग्रामीण गरीबों को जीवनयापन के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना समय की मांग और केंद्र सरकार का दायित्व है, सरकार ठीक इसके विपरीत कर रही है। अखिल भारतीय कमेटी का दृढ़ मत है कि यह प्रस्तावित विधेयक ग्रामीण गरीबों के जीवनयापन के अधिकार पर हमला है।

हम सभी मेहनतकशों से अपील करते हैं कि वे आगे आयें और केंद्र की भाजपा सरकार के इस जनविरोधी व मजदूर-विरोधी प्रयास को विफल करने के लिए अंत तक संघर्ष करें।''

एसयूसीआई (सी) ने कहा —महिला डाक्टर से माफी मांगें बिहार के मुख्यमंत्री

पटना(बिहार), 18 दिसम्बर: 15 दिसम्बर को मुख्यमंत्री सचिवालय में नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला चिकित्सक का हिजाब खींचे जाने की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इस संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं। इस शर्मनाक आचरण की जितनी निंदा की जाये, कम है।

उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ही राज्य की महिलाओं के साथ ऐसा अशोभनीय और बेशर्मीभरा आचरण करने लगें, महिलाओं की गरिमा और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने लगें, तब राज्य में महिलाओं पर हो रहे जुल्म-अत्याचार और उनके साथ की जा रही अश्लील हरकतों पर कैसे अंकुश लगेगा?

कॉमरेड सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि वे अपने इस बेशर्मीभरे आचरण के लिए उस महिला डाक्टर से अविलंब माफी मांगें।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**